बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 197 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 22 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

मिशन कचरा मुक्त दिल्ली में सीएम रेखा को मिली बड़ी कामयाबी, 1 साल में साफ करवाया 74 लाख मीट्रिक टन कचरा

नई दिल्ली। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को राजधानी दिल्ली को भलस्वा, गाजीपुर और ओखला के डंपसाइट्स (कचरे के पहाड़ों) से मुक्त कराने के अभियान में एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। सीएम रेखा के कुशल नेतृत्व में दिल्ली प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कचरा निपटान के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसे लेकर जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक रिकॉर्ड 74.11 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को बायोमाईनिंग तकनीक के जरिए पूरी तरह साफ किया जा चुका है। इससे इन डंपसाइट्स के आसपास रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी। आधुनिक मशीनों और बेहतर मैनेजमेंट के चलते दिल्ली के प्रमुख डंपसाइट्स पर अब काफी कम कचरा बचा है।

दिल्लीवालों को रेखा सरकार का तोहफा- अब 1.20 लाख आय वाले भी बनवा सकेंगे राशन कार्ड, 7.71 लाख अपात्र नाम हटे

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों और नए लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने 7 लाख 71 हजार 384 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए हैं, ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से राजधानी में गरीबों के नए राशन कार्ड नहीं बनाए गए, जिससे जरूरतमंद लोग दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे।

अब सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया के जरिए नए राशन कार्ड बनाने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय विजन के तहत कराए गए ऑडिट में पता चला कि करीब 1 लाख 44 हजार लोग ऐसे थे, जिनकी आय तय मानकों से यादा थी। इसके बाद सरकार ने 7 लाख 71 हजार 384 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए हैं, ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। सीएम ने कहा कि 15 मई से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी। राशन वितरण भी बायोमेट्रिक तरीके से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और सही व्यक्ति तक पूरा राशन पहुंचे।

फूड सिक्योरिटी रूल 2013 दिल्ली में लागू

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में फूड सिक्योरिटी रूल 2013 को अब पूरी तरह लागू कर दिया गया है। लोग अपने घर के पास स्थित सुविधा केंद्रों पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार की आय प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्यों का विवरण देना होगा।

दिल्ली में आए सीमा बढ़ाएगी सरकार

सरकार ने राशन कार्ड के लिए आय सीमा भी बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे आगे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये तक करने की तैयारी चल रही है।

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

लोग edistrict.delhigovt.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिला स्तर की समितियां करेंगी।खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब पात्र लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर सही तरीके से राशन मिलेगा।

दिन ही नहीं रात में भी सितम- दिल्ली में मई की सबसे गर्म रात, टूटा 14 साल का रिकॉर्ड

नई दिल्ली । दिल्ली में मई महीने की अब तक की सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जब न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार यह पिछले लगभग 14 वर्षों में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है। इससे पहले 26 मई 2012 को न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सफदरजंग और लोधी रोड सहित कई स्टेशनों पर रात में गर्म मौसम की स्थिति रही। गर्म रात तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। स्टेशनों के अनुसार सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक है। रिज में 30.6 डिग्री (4.4 डिग्री अधिक), पालम में 30.5 डिग्री (3.4 डिग्री अधिक), लोधी रोड में 29.6 डिग्री (4.6 डिग्री अधिक) और आयानगर में 27.4 डिग्री सेल्सियस (0.7 डिग्री अधिक) दर्ज किया गया। शहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है और दिन में लू चलने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता भी सुबह 9 बजे 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 0-50 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' श्रेणी में आता है।

बीजेपी नेता राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कहा- यह प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं

नई दिल्ली । राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और कहा कि राघव चड्ढा के व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं बनता. उनकी आलोचना उनके राजनीतिक फैसले को लेकर और बीजेपी में जाने को लेकर की जा रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद राघव चड्ढा की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री को हटाने की मांग की गई थी. हाई कोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों का कमर्शियल इस्तेमाल और आलोचना करने में अंतर है. दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा कि आपके राजनीतिक फैसले और बीजेपी में जाने की आलोचना हो रही है. प्रथम दृष्टया इसमें व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं बनता. कोर्ट ने कहा निस्संदेह आज़ादी के समय से ही हम आरके लक्ष्मण के कार्टून देखते आए हैं. उस दौर में शायद सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली नहीं था, जितना आज हो चुका है. जानकारी के लिए बता दें कि राघव चड्ढा की याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एआई-जनरेटेड डीपफेक, छेड़छाड़ वाले वीडियो, फैब्रिकेटेड भाषण और भ्रामक सामग्री को हटाने की मांग की गई है. कोर्ट ने राघव चड्ढा से पार्टी बदलना एक सार्वजनिक फैसला है, व्यक्तिगत नहीं.

अदालत ने एआई से बने वीडियो पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इन वीडियो पर आपत्ति है, तो विशेष याचिका दाखिल करें. व्यापक रूप से रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती. बता दें राघव चड्ढा की ओर से अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का हवाला देते हुए अज्ञात उल्लंघनकर्ताओं और सोशल मीडिया/ इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स, जिनमें Meta, X और Google शामिल हैं, को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों पर व्यापक रूप से प्रसारित किए जा रहे फर्जी, एआई-जनरेटेड और डीपफेक कंटेंट को तत्काल हटाने और ब्लॉक करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि संबंधित सामग्री दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राघव चड्ढा की प्रतिष्ठा व व्यक्तित्व अधिकारों को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली है. याचिका में यह भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक तकनीक का अनधिकृत इस्तेमाल कर छेड़छाड़ की गई सामग्री तैयार करना और प्रसारित करना न केवल कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि इससे अपूरणीय प्रतिष्ठात्मक क्षति भी हो रही है.

इबोला के बढ़ते खतरे के बीच भारत और अफ्रीकी संघ का नई दिल्ली शिखर सम्मेलन स्थगित

नई दिल्ली । अफ्रीका के कई हिस्सों में इबोला वायरस फैल रहा है. अब इसको देखते हुए 28 मई से दिल्ली में होने वाले अफ्रीकी संघ और भारत का एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा है. दोनों पक्षों ने आज एक बयान में यह जानकारी दी. अफ्रीका के कई हिस्सों में घातक इबोला वायरस के मामले सामने आए हैं, जिनमें से नया मामला कांगो लोकतांत्रिक गणराय के दक्षिण किवू प्रांत से आया है. भारत और अफ्रीकी संघ चौथे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे थे, तभी दोनों पक्षों ने अफ्रीका की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अफ्रीका सीडीसी और संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों को समर्थन सहित पूरे महाद्वीप में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निरंतर सहयोग के महत्व की पुष्टि की. बयान में यह भी कहा गया है. सरकार ने कहा कि शिखर सम्मेलन की नई तिथियों को आपसी परामर्श के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा और उचित समय पर सूचित किया जाएगा. शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का निर्णय भारत और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष तथा अफ्रीकी संघ आयोग के बीच हुए परामर्श के बाद लिया गया. सरकार ने कहा, इन परामर्शों के बाद, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि चौथे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करना उचित होगा. भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा मध्य अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैले इबोला के प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद केंद्र ने देश भर में निगरानी और तैयारियों के उपायों को भी तेज कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, रायों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगमन से पहले और बाद की स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन प्रोटोकॉल, केस प्रबंधन, रेफरल तंत्र और लैबरोटरी टेस्ट पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसओपी) के साथ सभी स्तरों पर तैयार रहने के लिए कहा गया है. अंतर्राष्ट्रीय सतर्कता की आवश्यकता इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि इबोला वायरस एक समान नहीं है, बल्कि यह अलग-अलग वायरल स्ट्रेन के रूप में प्रकट होता है. इनमें से प्रत्येक की घातकता, फैलने की गति और चिकित्सा अलग-अलग हैं. इस विशिष्ट स्वास्थ्य संकट का मुख्य कारण बंडीबुग्यो वेरिएंट है, जो इसका एक कम प्रचलित रूप है और ऐतिहासिक रूप से कुख्यात जैरे स्ट्रेन की तुलना में बहुत कम बार सामने आता है. इसने 2014 से 2016 तक पश्चिम अफ्रीका में महामारी फैल गई थी.

आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव की जरूरत, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला

नई दिल्ली । कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्थव्यवस्था पर नए ज्ञान की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ज्ञानेश (मुख्य चुनाव आयुक्त) के जरिए चुनाव मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर उन्हें नए ज्ञान की जरूरत है। उन्होंने कहा हमें इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में बड़े बदलाव की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार के पास आइडिया खत्म हो गए हैं। अब तो सरकार के समर्थक भी सार्वजनिक रूप से अपनी चिंताएं जाहिर करने लगे हैं। जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि देश में महंगाई का अनुमान बढ़ गया है और विकास दर के अनुमान में गिरावट आई है। विदेशी निवेश (स्रष्ठह्ल) लगातार कम हो रहा है। सप्लाई चेन का प्रबंधन इतना खराब है कि प्रधानमंत्री खुद उपभोक्ताओं से अपनी खपत कम करने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस लंबे समय से निवेश के खराब माहौल पर आवाज उठा रही है। कांग्रेस नेता के अनुसार, निजी निवेश बढ़ाए बिना आर्थिक विकास को तेज नहीं किया जा सकता। निजी निवेश इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि लोगों की वास्तविक मजदूरी स्थिर है। इससे बाजार में सामान की मांग कम हो गई है। जब मांग ही नहीं होगी, तो कंपनियों के

पास निवेश करने का कोई कारण नहीं बचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स नोटिस, छापेमारी और जांच एजेंसियों के डर की वजह से निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल है। चीन से होने वाले भारी आयात की वजह से स्थानीय सामान की मांग खत्म हो रही है।

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए व्यापार का केंद्रीकरण किया जा रहा है। इस क्रोनीइम का सबसे चमकदार उदाहरण मोदानी है। कॉरपोरेट जगत के पास स्वतंत्र रूप से निवेश करने और उससे जुड़े जोखिम उठाने का बहुत कम इंसेंटिव बचा है, क्योंकि मुनाफा मोदी सरकार के चंदा लो, धंधा दो काउंटर पर भुगतान करके भी आसानी से कमाया जा सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स की दरें सबसे कम हैं और कंपनियों की कमाई रिकॉर्ड स्तर पर है। शेयर बाजार भी ऊपर दिख रहा है, लेकिन जमीन पर निवेश गायब है। जो लोग निवेश कर सकते हैं, वे विदेशों का रुख कर रहे हैं। निवेश की बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन वे असल में कितनी पूरी होती हैं, यह एक बड़ा सवाल है। रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इटली की प्रधानमंत्री को टॉफी बांटने और आत्म-महिमामंडन में व्यस्त हैं, जबकि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है।

लुंबिनी और कपिलवस्तु को वैश्विक पहचान के लिए व्यापक अभियान की जरूरत

भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी और ऐतिहासिक धरोहर कपिलवस्तु को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। लुम्बिनी केवल नेपाल की पहचान नहीं, बल्कि विश्व शांति, आध्यात्मिक चेतना और मानवता का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस स्तर पर इसका विकास और प्रचार होना चाहिए था, वह अब तक नहीं हो सका। यह बातें लुम्बिनी विकास कोष के निवर्तमान सदस्य राजेश ज्ञवाली ने कही। उन्होंने कहा कि आज भी लुम्बिनी विकास की प्रतीक्षा में है। राज्य ने बजट तो आवंटित किया है, मगर वह पर्याप्त नहीं है और उसका बड़ा हिस्सा प्रशासनिक खर्चों में समाप्त हो जाता है। वास्तविक विकास, आधारभूत संरचना और पर्यटन प्रवर्द्धन की दिशा में अपेक्षित गति दिखाई नहीं दे रही। उनके अनुसार लुम्बिनी को केवल दिखावे का विषय बनाकर छोड़ दिया गया, जबकि इसे विश्व शांति के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए गंभीर और दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। राजेश ज्ञवाली ने कहा कि लुम्बिनी को धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए यह आस्था और जागरण का केंद्र है, जबकि अन्य लोगों के लिए भगवान बुद्ध के उपदेश मानव जीवन का मार्गदर्शन है। यदि लुम्बिनी को शांति के वैश्विक संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इससे नेपाल के पर्यटन क्षेत्र को भी नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने राज्य की नीतियों पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि लुम्बिनी विकास कोष में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की पर्याप्त भागीदारी न होना भी विकास में बड़ी बाधा है। यदि रूपन्देही, नवलपरासी और कपिलवस्तु के स्थानीय एवं जिम्मेदार व्यक्तियों को नेतृत्व में अवसर दिया जाए तो जवाबदेही बढ़ेगी और विकास कार्यों में गति आएगी। बाहरी लोगों को सीमित अवधि के लिए नियुक्त करने से वे क्षेत्र की वास्तविकता समझ ही नहीं पाते और समय समाप्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि विश्वभर में रहने वाले प्रवासी नेपाली समुदाय को लुम्बिनी के विकास अभियान से जोड़ा जाए। दुनिया के अधिकांश देशों में बसे नेपाली लुम्बिनी और बुद्धभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। यदि राज्य और लुम्बिनी विकास कोष सही नीति और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े तो प्रवासी नेपाली आर्थिक सहयोग, प्रचार-प्रसार और निवेश के माध्यम से ऐतिहासिक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने एक व्यक्ति, एक सौ डॉलर जैसे अभियान चलाने का सुझाव देते हुए कहा कि यह केवल उदाहरण है, मगर इसी प्रकार के रचनात्मक अभियानों से विश्वभर के नेपाली समुदाय को लुम्बिनी विकास से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही दूतावासों और प्रवासी संगठनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार अभियान चलाना भी अत्यंत आवश्यक है। राजेश ज्ञवाली ने कहा कि लुम्बिनी आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन पूर्वाधार का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अलग-अलग आर्थिक स्तर के पर्यटकों के लिए आधुनिक होटल, आध्यात्मिक केंद्र, सांस्कृतिक स्थल और अन्य सुविधाएँ विकसित करनी होंगी। इसके लिए प्रवासी नेपाली निवेशकों को आकर्षित करने की भी योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि निकट भविष्य में विश्व युवा बौद्ध सम्मेलन तथा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित करने की पहल की जानी चाहिए, ताकि लुम्बिनी को विश्व बौद्ध समुदाय के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। अंत में उन्होंने जोर देकर कहा कि संपूर्ण बुद्ध सर्किट की दीर्घकालीन योजना तैयार कर बुद्ध सर्किट से जुड़े नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों और सभी सरोकारवालों के साथ व्यापक संवाद, गोष्ठी और समन्वय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार, स्थानीय समुदाय, प्रवासी नेपाली और निजी क्षेत्र मिलकर साझा अभियान चलाएँ तो लुम्बिनी और कपिलवस्तु आने वाले समय में विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक नई और सम्मानजनक पहचान स्थापित कर सकते हैं।

सम्पादकीय...

सोने का त्याग करें, न, न नींद का नहीं

सरकार जी ने देश की जनता से अपील की है। अपील की है कि सोने का त्याग करें। नहीं, नहीं, उन्होंने सोने मतलब नींद के त्याग का जिक्र नहीं किया है। वे आपको जगाना नहीं चाहते हैं। वे तो चाहते हैं कि आप सोते रहें। आप जब तक सोयेंगे, सरकार जी सुरक्षित रहेंगे। जिस दिन आप जाग गए, उनकी सीट असुरक्षित हो जाएगी। तो आप नींद में रहें, जागें नहीं। सरकार जी आपको जगाने की बात नहीं कर रहे हैं। वह तो सोना धातु, स्वर्ण यानी गोल्ड, की बात कर रहे हैं। देश मुश्किल में है। यह मुश्किल में तो दो महीने से ज्यादा से है पर तब सरकार जी जप रहे थे। जब देश में कहीं भी चुनाव हो तो सरकार जी को सिर्फ चुनाव ही दिखता है। बाकी सबकुछ सरकार जी भूल जाते हैं। सरकार जी की आंख अर्जुन की आंख बन जाती है। इस बार सरकार जी बस बंगाल ही देख रहे थे, बाकी सब धुंधला गया था। सरकार जी को न तो देश दिख रहा था और न ही जनता। जनता को गैस का सिलेंडर मिल नहीं रहा है पर सरकार जी कह रहे थे कहीं कोई कमी नहीं है। जनता पेट्रोल पंपों पर लाइनों में लगी थी पर सरकार जी लाइन लगा कर रैलियां कर रहे थे। सरकार जी को तो बस चुनाव ही दिख रहे थे। यह संकट आया क्यों। लड़ाई की वजह से। अमरीका इजराइल-ईरान की लड़ाई की वजह से। पर असली जिम्मेदार नेहरू हैं। अब यह तो आप जानते ही हैं कि जिम्मेदारी, जिम्मेदार लोगों की ही होती है इसलिए हमारे सरकार जी किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। न तो सरकार जी बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं और न ही बेरोजगारी के लिए। वे तो दो समुदायों के बीच में वैमनस्य बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार नहीं हैं। जब सरकार जी किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हैं तो देश के इन हालात के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। इन हालात के लिए भी नेहरू ही जिम्मेदार हैं। नेहरू ने दशकों पहले कह दिया था कि कोरिया के युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो इस अमरीका, इजराइल-ईरान युद्ध से भी महंगाई बढ़ेगी ही। ऐसा नहीं है कि सरकार जी ने इस संकट को टालने के लिए कुछ नहीं किया। बहुत कुछ किया। सरकार जी ने क्या क्या नहीं किया। अमरीका को तो बाप पहले से ही बना दिया था, इजराइल को भी वहां जा कर बाप (फादर लैंड) बना लिया। ईरान से भी सदियों पुरानी दोस्ती तोड़ दी। सरकार जी ने उससे ऐसी कुट्टी की कि वहां के सदर की हत्या के अवसर पर, एक सौ साठ से अधिक बच्चों पर बम गिरने के दुःख पर भी दुःख नहीं जताया। सरकार जी ने यह किसके लिए किया। देश के लिए ही ना। बताओ सरकार जी इससे ज्यादा कर ही क्या सकते थे। इतिहास सरकार जी के इस कारनामे का सदा जिक्र करेगा। पर फिर भी देश पर संकट आ ही गया। सरकार जी तो कहना चाहते हैं कि लोग सोना नहीं खरीदें। वैसे तो सोने चांदी की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि कोई सोना खरीदने के बारे में बस सोच ही सकता है। इससे आगे की क्रिया मुश्किल ही है। सोना न खरीदने की सलाह के बाद सरकार जी ने सोने के आयात पर शुल्क भी बढ़ा दिया। जिससे सोना और महंगा हो गया और सोच से भी बाहर हो गया। उस पर देश में गरीबी इतनी जबरदस्त है कि अस्सी करोड़ लोग फ्री के राशन पर जिन्दा हैं। गरीबों की संख्या को सरकार जी ने पिछले छः साल से स्थिर रखा है। थोड़ी भी कम की हो तो बताओ। आज भी अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त पांच किलो अनाज मिल रहा है। छः साल पहले भी इतने ही लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा था।

व्यापक अभियान

मुंबई के लिए मुसीबत बने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पुलिस और प्रशासन ने कड़ा सबक सिखाकर देश की आर्थिक राजधानी को बड़ी राहत दिलाई है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर इलाके में पश्चिम रेलवे द्वारा चलाया जा रहा अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान न केवल रेलवे भूमि को मुक्त कराने की दिशा में अहम कदम साबित हुआ, बल्कि इस कार्रवाई ने यह भी उजागर कर दिया कि किस तरह अवैध कब्जाधारी कानून व्यवस्था को चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटते। कार्रवाई के दौरान पुलिस और रेलवे अधिकारियों पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिससे एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि देश के किसी भी हिस्से में अतिक्रमण हटाने या अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलते ही इन घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के पास अचानक इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं उल्लेखनीय है कि पश्चिम रेलवे ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के निकट गरीब नगर में फैले अवैध कब्जों को हटाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। यह मुंबई में रेलवे की अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई मानी जा रही है। रेलवे के अनुसार लगभग पांच हजार दो सौ वर्ग मीटर भूमि को खाली कराया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब छह सौ करोड़ रुपये आंकी गई है। यह इलाका हार्बर लाइन की पटरियों और बिजली व्यवस्था के बेहद करीब पहुंच चुका था, जिससे रेल संचालन और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यहां कई बहुमंजिला झुग्गियां फुटओवर पुलों की ऊंचाई से भी ऊपर तक बना दी गई थीं। इससे भविष्य की रेलवे परियोजनाओं और ट्रेनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। रेलवे लंबे समय से इस भूमि को खाली कराना चाहता था, क्योंकि बांद्रा स्टेशन और बांद्रा कुर्ला परिसर के पास स्थित यह इलाका रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया वर्ष 2017 से पहले शुरू हो चुकी थी। सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 27 नवंबर 2017 को बेदखली आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद मामला बंबई उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। इस वर्ष 29 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने अवैध अतिक्रमण हटाने की अनुमति दी थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी इस आदेश पर रोक नहीं लगाई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। पश्चिम रेलवे ने करीब पांच सौ झुग्गियों को हटाने के लिए चिन्हित किया, जबकि संयुक्त सर्वेक्षण में पात्र पाए गए लगभग एक सौ ढांचों को फिलहाल नहीं छुआ गया। रेलवे का कहना है कि भविष्य में इस जमीन का उपयोग उपनगरीय और लंबी दूरी की रेल सेवाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा। कार्रवाई को सफल बनाने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। करीब चार सौ पुलिसकर्मी, चार सौ रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस के जवान तथा लगभग दो सौ रेलवे अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए। बांद्रा स्टेशन और बांद्रा टर्मिनस के आसपास कई रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे भारी यातायात जाम लग गया और यात्रियों को सामान लेकर पैदल चलना पड़ा। शुरुआत में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, लेकिन दूसरे दिन दोपहर बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। अधिकारियों ने जब एक अवैध मस्जिद और वहां लगाए गए निजी दूरसंचार टावर को हटाने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासनिक टीमों पर पत्थर, बर्तन और अन्य सामान फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस हिंसा में सात पुलिसकर्मी और छह प्रदर्शनकारी घायल हुए। पुलिस ने दस लोगों को हिरासत में लिया और निर्मल नगर पुलिस थाने में गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। घायलों का उपचार भाभा अस्पताल और वीएन देसाई अस्पताल में कराया गया। एक पुलिसकर्मी और एक प्रदर्शनकारी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, हालांकि दोनों की हालत स्थिर बताई गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिनव देशमुख ने चेतावनी दी है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर कुछ निवासियों ने दावा किया कि वह कई दशकों से यहां रह रहे थे और उनके पास हाउस टैक्स, वाटर टैक्स तथा बिजली कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज भी हैं। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ईद से ठीक पहले की गई कार्रवाई ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि इन दावों और मानवीय पक्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अवैध कब्जों के खिलाफ हर कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं क्यों सामने आती हैं चाहे देश का कोई भी राज्य हो, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन पर हमला करना अब एक तयशुदा रणनीति जैसा दिखाई देता है। इससे साफ है कि कुछ तत्व कानून व्यवस्था को बिगाड़कर सरकारी कार्रवाई को रोकना चाहते हैं। मुंबई जैसे संवेदनशील और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर में इस तरह की हिंसा न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और शहरी व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चुनौती भी है।

छात्र और असंवेदनशील तंत्र

कोटा के 'कोचिंग कारखानों' से समाचार है कि नीट-यूजी की परीक्षा की दोबारा तैयारी करने के लिए देश भर से आकांक्षी वहां लौट रहे हैं। इस परीक्षा की आयोजक एनटीए ने पेपर लीक होने के बाद तीन मई को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी थी। अब यह 21 जून को दोबारा रखी गई है। 22 लाख छात्र और छात्राएं जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में बैठे थे, को दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। दोबारा कोटा या दूसरे कोचिंग सेंटरों में जाना पड़ेगा। पैसे खर्चने पड़ेंगे। रात-रात जागना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक बोझ बढ़ेगा। लय भी टूट जाती है। टेंशन से उम्मीदवार और उनके परिवारों को दोबारा गुजरना पड़ेगा। इसलिए कि कुछ भ्रष्ट लोगों ने पेपर लीक कर दिया। 'टेलीग्राम' और 'वॉटसअप' के द्वारा इसे प्रसारित कर दिया गया। लाखों रुपए की डील की गई। लातूर के एक कोचिंग सेंटर के मालिक को पकड़ा गया है। सीबीआई ने अदालत को बताया है कि उसे परीक्षा से 10 दिन पहले पेपर मिल गया था। 10 दिन पहले सब कुछ इतना सुविधाजनक है अब कुछ गिरफ्तारियां की गईं हैं पर इसका फायदा क्या है क्या स्टूडेंट्स के जो दिन, जो मेहनत, जो पैसा खर्च हो चुके हैं, वह लौटाए जा सकते हैं जिस टैंशन से वह गुजरे हैं बहुत परीक्षार्थी समाज के उस तबके से हैं जो बहुत समृद्ध नहीं हैं। उन पर क्या गुजरेगी दोबारा तैयारी के लिए साधन कहां से आएंगे कोचिंग सेंटर वालों की जरूर मौज लग गई होगी। यह भी हमारी विशिष्टता ही कही जाएगी कि यहां कोचिंग सेंटर का पूरा नेटवर्क है। कई सौ करोड़ रुपये का धंधा है। दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं है। नीट-यूजी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। 22 लाख परीक्षा में बैठे थे जबकि केवल 129000 ही मेडिकल सीटें हैं। डाक्टर व्यवसाय का यहां बहुत आकर्षण है पर हर बच्चा डाक्टर नहीं बन सकता। सब यह जानते हैं इसलिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। यह स्पर्धा कितना मानसिक तनाव पैदा करती है यह इस बात से पता चलता है कि परीक्षा रद्द होने के बाद हताशा में 4 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। इन्होंने आत्महत्या इसलिए नहीं की कि वह पेपर नहीं देना चाहते थे या सफल नहीं हुए, उन्होंने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि पूरी तैयारी के बावजूद उनका पेपर रद्द हो गया। वह एक गले सड़े भ्रष्ट तंत्र से हार गए। अफसोस की बात है कि हमारे देश में पेपर लीक होने या परीक्षा रद्द करने की यह एकमात्र मिसाल नहीं है। ऐसा बार-बार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि 2014 के बाद 93 पेपर लीक हुए हैं। यह आंकड़ा कितना सही है मैं नहीं कह सकता, पर हर साल किसी न किसी बड़ी परीक्षा में धांधली का समाचार जरूर मिल जाता है। रेलवे, पुलिस भर्ती आदि की परीक्षा में गड़बड़ी की बहुत शिकायतें मिलती रहती हैं। कई प्रदेशों को अपनी परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। दो साल पहले 2024 में यही नीट-यूजी की परीक्षा का प्रश्न पेपर लीक हो गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने पर रोक लगा दी थी और 1000 से अधिक परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी थी। उनका कसूर क्या था इतने विशाल देश में ऐसी परीक्षाएं करवाना आसान काम नहीं है पर इसीलिए तो यह एजेंसी बनाई गई है। संसदीय समिति को बताया गया कि 2024 में एनटीए द्वारा आयोजित 14 में से 5 राष्ट्रीय परीक्षा में या तो पेपर लीक हुआ या कोई और अनियमितता पाई गई। एनटीए की तो विश्वसनीयता ही नहीं रही। इतने बड़े स्केल पर परीक्षा करवाना निश्चित तौर पर चुनौती है। डिजिटल प्रसार के कारण शरारत को रोकना और भी कठिन हो गया है। पर नीट का गठन ही इसलिए किया गया था ताकि मेडिकल परीक्षार्थियों को तनाव और कई जगह होने वाले एंट्रेंस टैस्ट से बचाया जा सके। पर वह तो उन चिन्ताओं को भड़काने में सफल रहे हैं। 2024 में जो गड़बड़ हुई से कोई सबक नहीं सीखा गया। 2024 की पेपर लीक के बाद भाजपा सरकार ने इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल विशेषज्ञों की कमेटी बनाई थी जिसका काम परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करना और इसे सुरक्षित रखने के सुझाव देना था। पर दो साल के बाद भी कमेटी के सुझावों पर अमल नहीं किया गया। तब की तरह अब फिर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है जो रोजाना गिरफ्तारियां कर रही है। अखबारों की सुर्खियों के लिए पूरा काम हो रहा है। पर अगर इससे ही सिस्टम सही होता तो दो साल के बाद धांधली न होती। क्या इसका इलाज विकेंद्रीकरण है जैसा यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रो. वी. एन. राजशेखर पिल्लै ने सुझाव दिया है उनका कहना है कि पूरी तरह से केंद्रीयकृत परीक्षा भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए सही नहीं है। उनके इस सुझाव पर गौर करने की जरूरत है। पर असली बात तो विश्वसनीयता की है। जब तक आंतरिक कमजोरियों को खत्म नहीं किया जाता कोई भी सिस्टम सही नहीं रहेगा। क्या कोई इलाज है के राधाकृष्णन कमेटी ने सिफारिश की थी कि पैन और पेपर टैस्टिंग से हट कर कम्प्यूटर बेस्ड टैस्टिंग शुरू करनी चाहिए। अब बताया जा रहा है कि अगले साल से नीट भी कम्प्यूटराइज्ड टैस्टिंग करेगी। यह सिस्टम कई पश्चिमी देशों में है। वहां तो कई जगह स्टूडेंट्स को आनलाइन पेपर भेज दिया जाता है और कोई ऊपर से निगरानी नहीं होती। पर चैट जीपीटी और एआई के जमाने में यह प्रणाली तो खुद ही चुनौती है। हमारा तंत्र जो खुद को नाकाबिल साबित कर चुका है, वह कैसे सम्भालेगा क्या और सख्ती की जरूरत है बुलडोजर जस्टिस चाहिए चीन में नकल या पेपर लीक को देशद्रोह माना जाता है। 7 साल की जेल है। हमारे यहां 5-10 वर्ष की कैद का प्रावधान है पर यह तब होगा अगर जाँच कर रही एजेंसी पूरी तरह से केस तैयार करेगी और न्यायपालिका जल्द से जल्द इन 'कॉक्रोच' को सजा देगी।

2024 के घोटाले के बाद सीबीआई ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया था जिनमें मास्टर माइंड, सरकारी अधिकारी और उम्मीदवार शामिल हैं पर अभी तक दो साल के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई। किसी को अदालत द्वारा सजा नहीं दी गई। क्या इस बार भी यही होगा इस वक्त जो सक्रियता दिखाई जा रही है वह मामला ठंडा पड़ने पर शांत हो जाएगीरात गई बात गई। लेकिन यहां मामला केवल पेपर लीक का ही नहीं। हर नागरिक को अपने दैनिक जीवन में इस भ्रष्ट और असंवेदनशील तंत्र का सामना करना पड़ता है। हमारी सड़कें क्यों टूटी रहती हैं अब तो गडकरी जी की हाईवे भी झटके देती हैं। बिहार में पुल क्यों टूटते रहते हैं 4 मई को गंगा के ऊपर विक्रमशिला सेतु की 33 मीटर की स्लैब गिर गई। 2021-2024 के बीच 26 बड़े पुल गिर गए। क्या किसी इंजीनियर या ठेकेदार को सजा दी गई सम्भावना नहीं के बराबर है। हमारा पानी दूषित है, जलवायु दूषित है। खान पान में मिलावट है। फलों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी दयनीय क्यों है, विशेष तौर पर देहात में। यही स्थिति स्कूल शिक्षा की है। कई प्रदेशों में सरकारी शिक्षा बेहतर करने की कोशिश हो रही है पर लाखों स्कूल जीर्ण हालत में हैं और पढ़े लिखे अनपढ़ पैदा कर रहे हैं। क्या इसका कारण है कि हमारे शासक अपने बच्चे विदेशों में पढ़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने इलाज के लिए वह विदेश जा सकते हैं। उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। क्या वह उससे इलाज करवाने के लिए तैयार होंगे जो लीक हुए पेपर या चीटिंग के द्वारा डाक्टर बने हैं यह भी नहीं कि यहां सब परीक्षा में धांधली होती है। हर साल यूपीएससी की परीक्षा होती है। पूरी तरह से सही, बिना किसी गड़बड़ के। लोगों का इस परीक्षा पर पूरा भरोसा है जो नीट रही बैठी है जबकि दोनों सरकार द्वारा गठित स्वायत्त संस्थाएं हैं। क्या इसका कारण है कि यूपीएससी के कामकाज में राजनीतिक दखल नहीं है और नीट में है असली समस्या है कि जवाबदेही नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का कहना है कि सरकार की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य बर्दाश्त की है। वह कहते हैं कि, «हम स्टूडेंटस के भविष्य से किसी प्रकार के खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे»। इसका मतलब क्या है आपके अधीन संस्थाओं में लगातार स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पूरी शिक्षा प्रणाली पर लोगों का विश्वास डोल रहा है। क्या यह इसलिए है कि शिक्षा प्राथमिकता नहीं, चुनाव जीतना है सारा ध्यान और जोर चुनाव जीतने पर है, व्यवस्था को सही करने पर नहीं अब तो लाल बहादुर शास्त्री को याद करना भी अजीब लगता है। दीवार पर फोटो टांग कर हम आत्म संतुष्ट हैं।

इस बीच जालंधर से अच्छा समाचार है कि ई-रिक्शा चालक का बेटा मुकेश पंजाब बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम और राज्य में तीसरे स्थान पर रहा है। मुकेश जैसे प्रतिभाशाली नौजवान देश में भरे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मुकेश भी मेडिकल करना चाहता है। सोच कर घबराहट होती है कि जब इसका और उसके जैसों का सामना इस तंत्र और इस माफिया से होगा तो कैसी हताशा पैदा होगी सोचने की बात है कि जिन्दगी की दहलीज पर बच्चों को क्या सबक सिखाया जा रहा है कि करप्शन और हेराफेरी ही ऊपर उठने का रास्ता है

खालिस्तानी गतिविधियों से सिखों की छवि को नुकसान

सिख धर्म विश्व के सबसे सम्मानित और मानवता की सेवा को समर्पित धर्मों में से एक माना जाता है। सरबत दा भला, सेवा, त्याग और भाईचारे का संदेश देने वाले सिख समुदाय ने दुनिया के हर कोने में अपनी मेहनत, ईमानदारी और मानव सेवा के कारण विशेष पहचान बनाई है। चाहे प्राकृतिक आपदाओं के समय लंगर सेवा हो, कोविड महामारी के दौरान मानवता की सहायता हो या समाज के कमजोर वर्गों के लिए निस्वार्थ योगदान सिख समाज ने हमेशा पूरी दुनिया को इंसानियत का संदेश दिया है। मगर आज माहौल कुछ और ही बनता जा रहा है और खालिस्तानी समर्थकों और कट्टरपंथियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है जिसके चलते समूचा सिख जगत शर्मसार होता दिखाई पड़ता है। श्री दरबार साहिब जो कि संसार भर में बसते गुरु नानक नाम लेवा के लिए आस्था का केन्द्र है और लाखों की गिनती में सिख ही नहीं गैर सिख श्रद्धालु भी बड़ी गिनती में यहां दर्शनों के लिए आते हैं। मगर बीते दिनों में जिस प्रकार गैर सिख श्रद्धालुओं को जिन्हें सिख मर्यादा की जानकारी का आभाव रहता है सेवादारों या फिर वालंटियर के तौर पर सेवा करने वालों के द्वारा बेईज्जत किया जाता है जैसे कि हाल की एक घटना में देखने को मिला कि एक गैर सिख कपड़ों सहित सरोवर में स्नान करने लगा तो बजाए उसे समझाने के सेवा पर तैनात शख्स उस पर टूट पड़ा और बहुत ही मंदभागी शब्दावली का प्रयोग किया जैसा कि सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ा। वहीं दरबार साहिब गलियारे में एक बेजुबान जो अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकता किसी निहंग के द्वारा उस पर ताबड़तोड़ कृपाण से हमला बोल दिया जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई हालांकि इसकी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई मगर सोशल मीडिया पर इसका खूब प्रचार हो रहा है जिसके चलते सिख धर्म शर्मसार होने के और कुछ नहीं कर सकता। पिछले कुछ वर्षों में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों ने वैश्विक स्तर पर सिख समाज की सकारात्मक छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कुछ कट्टरपंथी तत्वों द्वारा विदेशों में हिंसक प्रदर्शन, भारत विरोधी नारे, धार्मिक स्थलों के बाहर उग्र प्रदर्शन और अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने के कारण पूरी सिख कौम को अनावश्यक विवादों में घसीटने का प्रयास किया जा रहा है। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हाल के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां खालिस्तान समर्थक समूहों ने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की आड़ में कट्टरता और उग्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की। भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान, मंदिरों और धार्मिक स्थलों के बाहर तनावपूर्ण गतिविधियां तथा खुलेआम हिंसा भड़काने वाले बयान इन घटनाओं से केवल भारत की छवि को नहीं, बल्कि वैश्विक सिख समाज की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित किया है। सबसे गंभीर बात यह है कि दुनिया के अनेक देशों में आम लोग सिख धर्म और खालिस्तानी विचारधारा के बीच अंतर नहीं समझ पाते। कुछ कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों के कारण पूरे सिख समुदाय को संदेह की दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश सिख शांति, भाईचारे और राष्ट्रभक्ति में विश्वास रखते हैं। भारत की सेना, न्यायपालिका, राजनीति, उद्योग और सामाजिक सेवा में सिखों का योगदान हमेशा गौरवपूर्ण रहा है। ऐसे में कुछ अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों से पूरी कौम की पहचान प्रभावित होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूरत इस बात की है कि शांतिप्रिय और राष्ट्रवादी सिखों की आवाज को अधिक महत्व मिले, ताकि दुनिया के सामने सिख धर्म की वास्तविक पहचान और मूल भावना उजागर हो सके। सिख कौम की पहचान तलवार की धार से नहीं, बल्कि सेवा, साहस और बलिदान से बनी है। यदि कुछ लोग व्यक्तिगत या राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस पहचान को कट्टरता से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो इसका नुकसान केवल भारत को नहीं बल्कि पूरी सिख कौम को उठाना पड़ेगा।

एजुकेशन लंगर समय की जरूरत

सिख धर्म में लंगर की प्रथा गुरु नानक देव जी के समय से शुरु हुई जब उनके पिता ने 20 रुपये देकर उन्हें व्यापार करने हेतु भेजा तो वह उन पैसों से भूखे साधुओं को भोजन करवा आए, तभी से संसार में लंगर की प्रथा चली जो आज तक जारी है। संसार में कहीं भी अगर कोई शख्स भूखा हो तो उसे इस बात का पता रहता है कि गुरुद्वारा में जाकर उसे खाने के लिए लंगर और रहने के लिए स्थान मिल जाएगा। मगर धीरे धीरे यह प्रथा दिखावे में तब्दील होती चली गई। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि अपनी वाह वाही के चक्कर में सड़कों पर लंगर लगाए जाते हैं जिसका जरूरतमंदों को कोई खास लाभ नहीं होता और साथ ही लंगर की बेअदबी अधिक होती है।

नगर कीर्तनों के दौरान एक ही सड़क पर अनगिनत स्टाल लगा दिये जाते हैं जबकि वास्तव में अगर लंगर सेवा करनी हो तो एक दिन ना करके हरदिन उसे करना चाहिए। वहीं आज यह भी महसूस होने लगा है कि आज समय की जरूरत एजुकेशन लंगर लगाने की है जिस पर सिख संगत का ध्यान नहीं जा रहा। गुरु नानक पब्लिक स्कूल राजौरी गार्डन के चेयरमैन बलदीप सिंह राजा का मानना है कि एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है कि अनेक सिख परिवार ऐसे हैं जिन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद की आवश्यकता रहती है उन परिवारों को मदद समुदाय को मिलकर करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में भी अक्सर ऐसे केस आते रहते हैं जिन्हें राजौरी गार्डन गुरुद्वारा के सहयोग से मदद पहुंचाई जाती है। आज सिखों के अनेक विद्यायक संस्थान बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं सभी को मिलकर उनका हल निकालकर उन्हें संकट से उबारना चाहिए ना कि राजनीतिक लाभ की खातिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए उन्हें बर्बादी की राह पर धकेलना चाहिए।

जत्थेदार अकाल तख्त की युवा पीढ़ी को प्रेरणा

सिख धर्म में पिछले लम्बे समय से धर्म परिवर्तन किए जाने की बात गंभीर चिन्ता का विषय बना हुआ है, इतना ही नहीं फैशन प्रस्ती की आड़ में पंजाब की युवा पीढ़ी पतितपुने की ओर अग्रसर होती चली जा रही है पर किसी भी धार्मिक जत्थेबंदी के द्वारा इसे रोकने की ओर ध्यान ही नहीं दिया मगर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के द्वारा जिस प्रकार से युवा पीढ़ी जो पतितपुने की राह पर निकल चुकी है और स्वयं ही नहीं अपने बच्चों को भी सिखी से दूर कर दिया है उन बच्चों को सिखी के प्रति जागरूक करते हुए पुनः सिखी स्वरूप में आने की अपील की जा रही है, इतना ही नहीं उनके द्वारा जहां भी पतित सिख बच्चा दिखाई देता है उसे रोककर सिखी के लिए प्रेरित करते हैं जो कि एक सराहनीय कदम है। इसी प्रकार अगर हर धार्मिक नेता, प्रचारक, कथावाचक, रागी सिंह अपनी जिम्मेवारी समझते हुए पतित लोगों को सिखी में वापिसी के लिए प्रेरित करें तो निश्चित तौर पर सिखी का दायरा ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि भविष्य में युवा पीढ़ी सिखी से दूर हो जाएगी ही नहीं। इसके लिए देखा जाए तो सबसे अधिक दोषी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, गायक और कलाकार हैं जो स्वयं तो सिखी का त्याग कर ही चुके हैं उसके साथ साथ अपनी फिल्मों में इस प्रकार के दृश्य, डायलग फिल्माए जाते हैं जो युवा पीढ़ी को सिखी से दूर करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं उसके लिए भी जत्थेदार जी को ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घाती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/[illegible])

656 करोड़ के विकास उत्सव में बरहज उपेक्षित- सोनूघाट फोरलेन और मोहन सेतु फिर सूची से बाहर, जनता में मायूसी

देवरिया।

जनपद के बुनियादी ढांचे को संवारने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 655.45 करोड़ की 19 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। जिला मुख्यालय से लेकर पथरदेवा और रामपुर कारखाना तक नेताओं की चमक और प्रशासनिक होर्डिंग्स विकास की नई कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन इस भारी-भरकम बजटीय निवेश और उत्सव के बीच जनपद का ऐतिहासिक बरहज विधानसभा क्षेत्र खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। क्षेत्रीय जनता के लिए यह विकास की बरसात भी सूखी साबित हो रही है, क्योंकि क्षेत्र की दो सबसे बड़ी और बेहद जरूरी मांगें बरहज-सोनूघाट मार्ग का फोरलेन में चौड़ीकरण और बहुप्रतीक्षित मोहन सेतु का निर्माण इस बार भी मुख्यमंत्री के शिलान्यास व लोकार्पण की आधिकारिक सूची से रहस्यमयी तरीके से गायब हैं। बरहज और जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जनपद में जश्न का माहौल, लेकिन सुदूर अंचल की लाइफलाइन पर लोक निर्माण विभाग की बेरुखी बरकरार

डबल इंजन सरकार के नौ वर्ष पूरे होने के बाद भी अधूरा है पुल का निर्माण, फाइलों के चक्कर में उलझी क्षेत्रीय विकास की रफ्तार

सोनूघाट मार्ग इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक जीवनरेखा माना जाता है। रोजाना हजारों की संख्या में व्यापारी, छात्र, गंभीर मरीज और आम राहगीर इसी जर्जर मार्ग से होकर गुजरते हैं। लोक निर्माण विभाग की घोर उदासीनता के चलते वर्तमान में इस मुख्य मार्ग की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि गड्ढों और सड़कों का अंतर पूरी तरह समाप्त हो गया है। बरसात के दिनों में यह मार्ग जलभराव के कारण तालाब में तब्दील हो जाता है, तो गर्मियों में उड़ने वाले धूल के गुबार राहगीरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग का आरोप है कि विभाग ने इस महत्वपूर्ण मार्ग को केवल फाइलों में सीमित कर रखा है, जिसके कारण हर बार बजट आवंटन के समय बरहज की उपेक्षा की जाती है। इस उपेक्षा की सबसे बड़ी बानगी मोहन सेतु का अधूरा निर्माण है, जो सीधे तौर पर प्रशासनिक हीलाहवाली की गवाही दे रहा है। प्रदेश में भाजपा सरकार के नौ वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को है और जिले में सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक सत्ता पक्ष के ही प्रतिनिधि काबिज हैं। स्वयं मुख्यमंत्री गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं और इस अंचल की भौगोलिक स्थिति से भली-भांति परिचित हैं। इसके बावजूद मोहन सेतु का काम कछुआ गति से चलना विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जनता के बीच अब यह चर्चा आम हो चुकी है कि यदि पूर्ण बहुमत और साझा समन्वय की सरकार में भी एक अदद पुल और मुख्य मार्ग का कायाकल्प नहीं हो सकता, तो फिर विकास के इन बड़े आंकड़ों के दावों की प्रासंगिकता क्या है। आज जब मुख्यमंत्री भीमपुर गौरा के मंच से बटन दबाकर जनपद के अन्य हिस्सों की सड़कों को करोड़ों का बजट सौंप रहे होंगे, तब बरहज की जनता उम्मीद भरी नजरों से मंच की तरफ देख रही होगी। क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि हर चुनाव में यहां बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस बनी रहती है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी जो वर्तमान में जिले के विकास कार्यों को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार फील्ड मॉनिटरिंग कर रहे हैं, से भी क्षेत्रीय जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। यदि जिला प्रशासन इस जन-आकांक्षा को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर पर अलग से एक ठोस प्रस्ताव नहीं भेजता, तो करीब 656 करोड़ रुपये के इस महा-बजट के बीच बरहज के हिस्से केवल आश्वासनों का झुनझुना ही रह जाएगा।

देवरिया के विकास का ऐतिहासिक सवेरा : आज 655.45 करोड़ की 19 परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

देवरिया।

जनपद की परिवहन व्यवस्था, तकनीकी शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे की सूरत बदलने के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्वाह्न ठीक 10::25 बजे तहसील क्षेत्र के भीमपुर गौरा स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे।

वे जनपदवासियों को 655.45 करोड़ रुपये की लागत वाली 19 महत्वकांक्षी विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। इस वृहद सरकारी समागम में जहां एक ओर 116.54 करोड़ रुपये के बजट से पूरी हो चुकीं 8 जनकल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण होगा, वहीं दूसरी ओर भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 538.91 करोड़ रुपये की 11 नई कड़ियों का शिलान्यास किया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस महकमे ने मुख्यमंत्री के इस एक घंटे के सघन वीवीआईपी दौरे को लेकर आयोजन स्थल से लेकर सुरक्षा ग्रिड तक के सभी इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया है। इस पूरे विकास पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा जनपद की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर खर्च हो रहा है।

खोजी नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी देवरिया-कसया मार्ग को मिली है, जिसके कायाकल्प पर 292.07 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की जाएगी।

इसके अलावा, देवरिया-हाटा मार्ग के बड़े हिस्से (चैनेज 2.00 से 22.00 तक) के सुदृढ़ीकरण के लिए 74.47 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का आज भूमिपूजन होने जा रहा है। ये दोनों मार्ग वर्षों से भारी यातायात के दबाव और बदहाली से जूझ रहे थे, जिनके चौड़े होने से न केवल कुशीनगर और गोरखपुर की कनेक्टिविटी सुधरेगी, बल्कि स्थानीय व्यापार को भी एक नया पंख मिलेगा।

प्रचंड गर्मी डीजल पेट्रोल के लग रही कतार, परेशानी देख बैरंग लौट रहे लोग

महराजगंज।

जिले में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। शहर के अलावा जिले में अन्य स्थानों पर कई पेट्रोल पंपों पर या तो तेल सीमित मात्रा में दिया गया या फिर पूरी तरह स्टॉक खत्म होने की स्थिति बन गई। कई इलाकों में उपभोक्ताओं को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। गर्मी के कारण कतार में ज्यादा देरतक खड़े नहीं रह पाने के कारण तमाम लोग बगैर तेल लिए वापस चले गए। शहर में निचलौल रोड पर पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए आनंद कुमार कतार में पिछे खड़े थे। उनको भीड में आगे बढ़ना मुश्किल था। उन्होंने बताया कि बाबू जी को लखनऊ इलाज के लिए ले जाना है। करीब तीन जद्दोजहद के बाद उनको डीजल मिला तो रवाना हुए। इसी तरह से अन्य लोग भी परेशान रहे। सबसे अधिक परेशानी डीजल के लिए हो रही है। क्योंकि गैलन में डीजल अधिक भरवाया जा रहा है। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए खेत की सिचाई करनी पड़ रही है। अब पेट्रोल-डीजल एवं सीएनजी की बढ़ी कीमतों ने हालात और खराब कर दिए हैं। नतीजतन ऑटो चालक, छोटे व्यापारी, डिलीवरी करने वाले और नौकरीपेशा लोग अतिरिक्त बोझ उठाने को मजबूर हो रहे हैं। आटो चालक राजू ने बताया कि ईंधन के दाम बढ़ने से नया संकट आ गया है। डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ने से ऑटो में 15 रुपये प्रति सवारी से कम नहीं बैठा रहे हैं। पहले 10 रुपये भी ले लेते थे मगर अब उन्हें घाटा हो रहा है। कम दूरी पर भी 15 रुपये लेते हैं। चेहरी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म होने के कारण 'पेट्रोल नहीं है' का बोर्ड लगा दिया गया। फरेंदा लेहड़ा मंदिर रोड पर पंप में भी बुधवार दोपहर 12 बजे के बाद पेट्रोल खत्म हो गया, जिससे लोगों को इधर-उधर भटकना पड़ा। शहर के साथ-साथ हाईवे पर स्थित कई पेट्रोल पंप भी बृहस्पतिवार को ड्राई नजर आए। पेट्रोल नहीं होने के कारण कुछ पंपों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डीलर्स का कहना है कि जल्द ही सभी पंपों पर आपूर्ति पूरी तरह बहाल हो जाएगी। हालांकि, इस अस्थायी किल्लत ने एक बार फिर आपूर्ति व्यवस्था की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि स्टॉक में कोई कमी नहीं है लेकिन लोग भंडारण कर रहे हैं, जिसके कारण किल्लत हो रही है। जिलापूर्ति अधिकारी एपी सिंह ने बताया की सभी पंपों पर आपूर्ति जारी है और कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। लोगों से अपील है कि वह अपनी जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल और डीजल लें ताकि किसी तरह की समस्या न आए।

पुरस्कार पाकर खिले बच्चों के चेहरे

भटनी देवरिया।

विद्यालय में गूंजा उत्साह, समर कैंप में बच्चों ने खेल -मस्ती और स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाया आनंद

के. के. पब्लिक एकेडमी सीनियर सेकेंडरी में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह एवं समर कैंप का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के साथ विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा भी की गई। समारोह का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बी. के. श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक अजय वर्मा एवं अरुण तिवारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में प्ले-वे से कक्षा 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी एवं शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेडल, प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं की छात्रा पिंकी सिंह ने 90.4 प्रतिशत तथा कक्षा 12वीं के छात्र आयुष विश्वकर्मा ने 93.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। विद्यालय प्रबंधन ने दोनों मेधावी विद्यार्थियों को मोमेंटो, प्रमाण पत्र, मेडल एवं चेक देकर सम्मानित किया तथा उनके अभिभावकों का भी सम्मान किया। समर कैंप के दौरान बच्चों ने विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में भाग लिया और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। समारोह का वातावरण उत्साह, गर्व एवं प्रेरणा से परिपूर्ण रहा।

सद्भावना क्लब ने परीक्षार्थियों के लिये की नि-शुल्क पेयजल सेवा

जौनपुर।

सद्भावना क्लब ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों की सुविधा हेतु शिया कालेज गेट के पास निःशुल्क शुद्ध पेयजल सेवा का आयोजन किया जहां भीषण गर्मी के बीच आयोजित इस जनसेवा कार्य की परीक्षार्थियों एवं स्थानीय लोगों ने सराहना किया। इस दौरान क्लब पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने परीक्षार्थियों को ठण्डा एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया तथा उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि सद्भावना क्लब हमेशा सामाजिक एवं जनहित के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और आगे भी ऐसे सेवा कार्य निरन्तर आयोजित किये जाते रहेंगे। इस अवसर पर अध्यक्ष डा. विवेकानन्द मौर्य, कोषाध्यक्ष विनीत गुप्ता, सचिव हर्ष माहेश्वरी, पूर्व अध्यक्ष लालजी यादव, पूर्व अध्यक्ष आशीष साहू, मधुसूदन बैंकर, डॉ अलमदार नजर, डा. एमपी बरनवाल, निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद रजा खां, संतोष अग्रहरि, अखिलेश अग्रहरि, ज्ञानेन्द्र पाल, रविन्दर यादव, चन्द्रेश मौर्य, अंश मौर्या, अवधेश यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

सादगी की मिसाल- ई-रिक्शा से पहुंचे उप जिलाधिकारी फरेंदा शैलेन्द्र कुमार गौतम

महराजगंज।

शासन की मंशा के अनुरूप जब प्रशासनिक अधिकारी वातानुकूलित कमरों और सरकारी गाड़ियों का तामझाम छोड़कर सीधे जनता के बीच पहुंचते हैं, तो न सिर्फ समस्याओं का त्वरित समाधान होता है बल्कि जनता का तंत्र पर भरोसा भी मजबूत होता है। कुछ ऐसा ही अनूठा नजारा बृहस्पतिवार को आनंदनगर क्षेत्र में देखने को मिला। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के सुलभ, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के आह्वान को धरातल पर उतारते हुए आज एक अधिकारी ने सादगी और कर्तव्यपरायणता की नई मिसाल पेश की।बृहस्पतिवार को एक पीड़ित अपने भूमि विवाद की समस्या लेकर पहुंचा था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी फरेंदा शैलेन्द्र कुमार गौतम ने किसी सरकारी वाहन या अमले का इंतजार करने के बजाय, सीधे आवेदक के ही ई-रिक्शा में बैठने का फैसला किया।

बिना किसी सुरक्षा गार्ड या अर्दली को साथ लिए, अधिकारी सीधे पीड़ित के साथ ई-रिक्शा में सवार होकर विवादित स्थल के निरीक्षण के लिए रवाना हो गए।

चौपाल सजी और मौके पर ही हुआ फैसला

अक्सर भूमि विवाद के मामले कोर्ट-कचहरी और तहसीलों के चक्करों में सालों-साल लंबित रहते हैं। लेकिन जब अधिकारी स्वयं ई-रिक्शा से मौके पर पहुंचे, तो वहां का माहौल ही बदल गया। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठाया गया। जमीन के कागजातों और वास्तविक स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद, दोनों पक्षों से बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत की गई। अधिकारी की इस संवेदनशीलता का असर यह हुआ कि दोनों पक्षों ने विवाद को भुलाकर आपसी सहमति बना ली। परिणाम स्वरूप, वर्षों से खिंच सकने वाले इस भूमि विवाद का मौके पर ही शांतिपूर्ण ढंग से स्थायी निस्तारण कर दिया गया।

ई-रिक्शा से भ्रमण- पर्यावरण संरक्षण और जमीनी हकीकत का मेल

इस अनोखे निरीक्षण के दौरान ई-रिक्शा का चयन केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश था। ई-रिक्शा से सफर करने के अनुभव को साझा करते हुए एसडीएम फरेंदा शैलेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचाने के संकल्प के क्रम में यह एक छोटा सा प्रयास था। ई-रिक्शा में भ्रमण करने से न सिर्फ सरकारी तेल की बचत हुई, बल्कि बंद शीशों वाली वीआईपी गाड़ियों से दूर, क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं और आमजनमानस के रोजमर्रा के संघर्षों को बहुत करीब से देखने व समझने का अवसर भी मिला।

मौके पर ही निपटाया भूमि विवाद, आम आदमी बन जाना तहसील का हाल

आम आदमी बनकर लिया तहसील का फीडबैक

विवाद का निस्तारण करने के बाद एसडीएम का यह औचक दौरा यहीं नहीं रुका। बिना किसी सुरक्षा घेरे (गार्ड या अर्दली) के जब वे नायब तहसीलदार के साथ आनंदनगर बाजार की सड़कों और तंग गलियों में घूमे, तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। एक आम नागरिक का भेष धरकर वे बाजार में दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय निवासियों के बीच जाकर खड़े हो गए।इस दौरान उन्होंने बेहद सामान्य ढंग से लोगों से बातचीत शुरू की और तहसील के कामकाज, कर्मचारियों के व्यवहार तथा सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति को लेकर जनता का %सीधा फीडबैक% लिया। चूंकि लोगों को यह भनक तक नहीं थी कि उनके सामने स्वयं अधिकारी खड़े हैं, इसलिए जनता ने भी बिना किसी डर, संकोच या दबाव के अपनी वास्तविक समस्याओं को साझा किया और तहसील की कार्यप्रणाली को लेकर बेबाक राय दी।

यह घटिया मानसिकता- राहुल गांधी पर भड़के शिवराज सिंह, पीएम मोदी का अपमान जनता माफ नहीं करेगी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी भाषा घटिया मानसिकता को दर्शाती है और जनता इसे माफ नहीं करेगी। हैदराबाद में बोलते हुए चौहान ने कहा कि यह घटिया मानसिकता का संकेत है जिसे पूरी दुनिया सम्मानित कर रही है और कई देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह घटिया मानसिकता का संकेत है। भारत के प्रधानमंत्री, जिन्हें पूरी दुनिया सम्मानित कर रही है और जिन्हें कई देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं, उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया उनके नेतृत्व की प्रशंसा कर रही है और देश उनके साथ खड़ा है। इस बीच, तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी को दिए गए उपहार को लेकर की गई आलोचना के लिए निशाना साधा। हैदराबाद में बोलते हुए, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री के इस कदम का बचाव करते हुए उपहारों के आदान-प्रदान को राजनयिक संबंधों में एक सामान्य प्रक्रिया बताया। राव ने कहा कि राजनयिक संबंधों में उपहारों का आदान-प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया है। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी को इटली के प्रधानमंत्री को टॉफी भेंट करने में विवाद क्यों दिख रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उपहार का राजनीतिकरण करना राहुल गांधी की घोर गैरजिम्मेदाराना हरकत है। राव ने कांग्रेस नेता को ऐसी टिप्पणियों से बचने और अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। उन्होंने आगे कहा कि हम राहुल गांधी को एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह व्यवहार करने की सलाह देते हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर लगी रोक, पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके का दावा

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी गई है। इसके संस्थापक अभिजीत दिपके ने यह दावा किया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत में सोशल मीडिया पर भारी संख्या में फॉलोअर्स लेकर सभी का ध्यान खींचा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच की तरह बताया था। बाद में उन्होंने सफाई दी और कहा कि उन्होंने सिर्फ फर्जी डिग्री वालों की आलोचना की थी। हालांकि, उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई, यह मामला वायरल ट्रेंड बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बन गए और देखते ही देखते वे वायरल हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर एक करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं एक्स अकाउंट पर कॉकरोच जनता पार्टी के दो लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि उनका एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है, लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट अभी सक्रिय है। आमतौर पर एक्स अकाउंट पर कानूनी आधार पर रोक लगाई जाती है। इसके लिए किसी अधिकृत निकाय द्वारा अकाउंट पर रोक लगाने की मांग करना जरूरी है। 15 मई को सीजेआई की कॉकरोच वाली टिप्पणी के बाद बनी इस पार्टी ने 21 मई आते-आते इंस्टाग्राम पर इसने फॉलोवर्स के मामले में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा तक को पीछे कर दिया है। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर 1.35 करोड़ फॉलोवर्स हैं। जो देश के दोनों बड़े राजनीतिक दलों से ज्यादा है। भाजपा के 88 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। वहीं, कांग्रेस के फॉलोवर्स की संख्या 1.33 करोड़ है। कॉकरोच जनता पार्टी को एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन बताया जा रहा है। भले ही यह आंदोलन व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ हो, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मुख्य मकसद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विफलताओं पर निशाना बनाया है।

उत्तराखंड के नैनीताल में बड़ा हादसा, खाई में गिरी कार; यूपी के पांच लोगों की मौत

नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में गुरुवार को भीषण हादसा हो गया। यहां भवालीगांव बाईपास पर एक कार खाई में गिर गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। कार यूपी की है। रेस्क्यू अभियान जारी है।

जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दोपहर करीब 2:15 बजे सेनेटोरियम- रातीघाट बायपास रोड, भवाली स्थित ढैला गांव से 500 मीटर पहले एक महिंद्रा कार (वाहन संख्या यूपी 32 क्यूयू 1874) अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। वाहन में कुल पांच लोग सवार थे। स्थानीय पुलिस एसडीआरएफ तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा संयुक्त रूप से राहत व बचाव अभियान चलाया गया। हादसे में एक बच्चे सहित दो पुरुष और दो महिलाओं की मौत हुई है। पुलिस एवं एसडीआरएफ, एसएसबी टीम द्वारा सभी शवों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य निरंतर जारी है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

चंडीगढ़ में बम ब्लास्ट की धमकी- स्कूलों-हरियाणा सीएमओ को उड़ाने की लिखी बात, अंबाला रेल ट्रैक पर करेंगे ब्लास्ट

चंडीगढ़ ।

चंडीगढ़ में कई स्कूलों को को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पहले के मामलों की तरह इस बार भी धमकी ईमेल के माध्यम से आई है। जिन स्कूलों को धमकी मिली है उनमें चितकारा स्कूल, स्ट्राबेरी स्कूल और डीपीएस स्कूल शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गईं और सघन तलाशी अभियान चलाया गया।

हरियाणा सीएम का भी जिक्र

धमकी भरी मेल में हरियाणा के सीएम नायब सैनी का नाम भी लिखा है। ईमेल में लिखा है कि स्कूलों में 1.11 बजे और सीएम सैनी के आफिस में 3.11 बजे धमाके होंगे। इसके अलावा लिखा गया है कि 6 जून तक अंबाला से दिल्ली रेलवे ट्रैक पर धमाके होंगे। धमकी भरे ईमेल में चंडीगढ़ को खालिस्तान बनाने की साजिश का जिक्र किया गया। साथ ही लिखा गया कि हमारा बच्चों से कोई बैर नहीं है। ईमेल के अंत में खालिस्तान नेशनल आर्मी लिखा हुआ है। अंत में उसी व्यक्ति का नाम लिखा है, जिसके नाम से पहले भी धमकी भरे मेल भेजे गए थे। पुलिस के अनुसार, धमकी भरा ईमेल किस आईडी से भेजा गया, इसकी जांच की जा रही है। साइबर सेल की टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ईमेल भेजने वाले की पहचान में जुटी है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी शहर के कुछ शिक्षण संस्थानों को इस तरह के ईमेल मिल चुके हैं, जिनमें कोई विस्फोटक नहीं मिला था।

लोगों में चिंता का माहौल

वहीं बार-बार स्कूलों और अन्य सरकारी संस्थान में बम की धमकी से लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि अब यह रोजमर्रा की बात हो गई है, इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन और भारत सरकार को अब कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए।

राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर भावुक हुए राहुल गांधी, बोले- आपका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी लूंगा

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और बचपन की एक निजी तस्वीर के साथ एक हार्दिक संदेश साझा किया। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि पापा, आपने जिस कुशल, समृद्ध और सशक्त भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। आपकी शिक्षाएं, आपके मूल्य और आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। कांग्रेस नेता ने पोस्ट में दो तस्वीरें भी साझा कीं। इनमें से एक तस्वीर राहुल गांधी और राजीव गांधी की बचपन की है, जिसमें पिता-पुत्र के बीच का एक निजी पल झलक रहा है, जो श्रद्धांजलि की भावुकता को दर्शाता है।

यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब देश भर में कांग्रेस के नेता राजीव गांधी को उनकी शहादत दिवस पर याद कर रहे थे और राष्ट्रीय राजधानी में उनके स्मारक, वीर भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। आज सुबह कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीर भूमि जाकर राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चे, मिराया और रायहान वाड्रा भी श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित थे। अशोक गहलोत, पी चिदंबरम, भूपिंदर सिंह हुड्डा और मुकुल वासनिक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक संक्षिप्त संदेश पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने राजीव गांधी को भारत का एक उल्लेखनीय सपूत बताया और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई सुधारों पर प्रकाश डाला।

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, रनवे से टकराया एअर इंडिया का विमान, 179 यात्री थे सवार

नई दिल्ली ।

दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग के समय हादसे का शिकार हो गया. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरते समय फ्लाइट AI2651 'टेल-स्ट्राइक' का शिकार हो गई. विमान का पिछला हिस्सा अचानक रनवे से टकरा गया. हालांकि पायलट ने स्थिति को संभाल लिया और सुरक्षित लैंडिंग पूरी की. विमान में सवार सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया. एअर इंडिया के इस विमान में 179 लोग सवार थे. यात्रियों से भरे इस विमान में पायलट को लैंडिंग के वक्त आगे उड़ रहे दूसरे विमान की वजह से wake turbulence महसूस हुआ जिसके चलते नियंत्रण प्रभावित हुआ और विमान की टेल रनवे से टकरा गई. विमान को जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया. इस घटना के चलते बेंगलुरु

से दिल्ली लौटने वाली फ्लाइट AI2652 को रद्द कर दिया गया है. एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की ग्राउंड टीम यात्रियों को हर जरूरी सहायता दे रही है. एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेक टर्बुलेंस जैसी स्थिति में पीछे आ रहे विमान की स्थिरता अचानक प्रभावित हो सकती है जिससे इस तरह की घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. एअर इंडिया ने कहा कि एयरलाइन इस घटना की पूरी जांच सरकारी नियमों और तय प्रक्रियाओं के तहत कर रही है. कंपनी ने कहा कि बेंगलुरु में उनकी टीम यात्रियों की हर संभव मदद कर रही है. एअर इंडिया ने यात्रियों को हुई इस असुविधा के लिए खेद जताया है और कहा है कि उनके लिए यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है.

कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान हैं, युवतियां हैं, उनका गुस्सा है - योगेंद्र यादव

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर योगेंद्र यादव ने कहा कि जो सरकार चुटकुला नहीं सह पा रही, इसका मतलब है कि वो खुद एक चुटकुला है. कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर पर सरकार ने जो बैन लगाया है, उससे एक बात साफ है कि ये बाहर से जितने भी ताकतवर दिखते हों, अंदर से खोखले हैं. घबराए हुए हैं. ये एक मोमेंट है. कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान हैं, युवतियां हैं, उनका गुस्सा है. आज हमारी एक ही ड्यूटी है कि उनके साथ खड़े हों. योगेंद्र यादव ने लोगों से अपील कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें. उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी शुरुआत है.

बस एक ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी हरकत न हो जिससे सरकार को मौका मिले. सरकार बहाने की तलाश में होगी. हमें वो बहाना नहीं देना है.

पुलवामा ग्रेनेड अटैक में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की हत्या

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को एक और बड़ा झटका लगा है. प्रतिबंधित आतंकी संगठन Al-Badr के प्रमुख कमांडरों में शामिल अरजमंद गुलजार उर्फ बुरहान हमजा मारा गया है. सूचना है कि अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वह लंबे समय से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में शामिल था और दक्षिण कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने वाले प्रमुख चेहरों में गिना जाता था. अरजमंद गुलजार मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नीपोरा इलाके का रहने वाला था. वह करीब 7 साल पहले वैध दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान गया था, जहां उसने आतंकी संगठन अल-बद्र जॉइन कर लिया. बाद में वह संगठन का ऑपरेशनल कमांडर बन गया और पाकिस्तान से बैठकर कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, फंडिंग और हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क चलाने लगा. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसे लंबे समय से मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा हुआ था.

पीएम मोदी ने की मंत्रिपरिषद के साथ योजनाओं की प्रगति और पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने गुरुवार को राजधानी में स्थित सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार के कई बड़े मंत्रालयों ने अपनी-अपनी प्रगति और कामकाज पर प्रस्तुति दी। इनमें कृषि, वन, श्रम, सड़क परिवहन, कॉरपोरेट मामलों, विदेश, वाणिज्य और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय शामिल रहे। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को साफ संदेश दिया कि सरकार के काम में तेजी और कुशलता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि फाइलों को बिना किसी अनावश्यक देरी के तेजी से आगे बढ़ाया जाए और कम समय में ज्यादा काम करने पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने शासन को और सरल बनाने और सुधारों पर जोर देने की बात कही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक करीब साढ़े चार घंटे तक चली। इस बैठक में सरकार के कामकाज, विकास योजनाओं और पश्चिम एशिया संकट के भारत पर असर जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

पीएम ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को दोहराया

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर मंत्रालय को पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ काम करना होगा। इस बैठक में उन मंत्रालयों पर भी चर्चा हुई जिनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। ऐसे मंत्रालयों को अपनी कमियों को दूर करने और कामकाज में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

पीएम मोदी को सफल विदेश दौरे के लिए दी गई बधाई

मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही में हुए पांच देशों के सफल दौरे के लिए उन्हें बधाई भी दी। इस दौरान विदेश मंत्री ने इस दौरे के परिणामों और इसके महत्व की जानकारी मंत्रियों को दी। यह दौरा संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली तक फैला हुआ था।

जनता को पिछले 12 वर्षों के काम-उपलब्धियां बताने के निर्देश

प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को यह भी निर्देश दिया कि वे जनता के बीच जाकर सरकार के पिछले 12 वर्षों के काम और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएं।

सूत्रों के अनुसार, यह बैठक सरकार के कामकाज की मध्यावधि समीक्षा (मिड-टर्म रिव्यू) के रूप में भी देखी जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।

ऊर्जा संकट के बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की परिस्थितियों के कारण तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर भारत सहित कई देशों पर पड़ रहा है। इस उच्चस्तरीय बैठक में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हुए। कुल मिलाकर यह बैठक सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा और भविष्य की दिशा तय करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

एनटीए बोला- नीट पेपर हमारे सिस्टम से लीक नहीं हुआ

संसदीय समिति ने पूछा- फिर दोबारा एग्जाम क्यों, डायरेक्टर जनरल जवाब नहीं दे पाए

नई दिल्ली। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक में पहुंचे। उधर देशभर में कई राज्यों में पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार को संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग में नीट परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कई सांसदों ने एनटीए के शीर्ष अधिकारियों से कड़े सवाल पूछे। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा कि नीट का पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ था और मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस पर कई सांसदों ने पूछा कि अगर पेपर एनटीए सिस्टम से लीक नहीं हुआ, तो बाहर कैसे आया और परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की जरूरत क्यों पड़ी। इस पर एनटीए के डीजी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। नीट-यूजी परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया। 12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री-एग्जाम का फैसला लिया गया।